वर्ष : 01 > अंक : 02 | RNi NO RAJHIN26/A8486 | ITIB | Hello@ankitinspiresindia.com | पृष्ठ : 8 > मूल्य: 2.00

इंडिया दैट इज भारत

साप्ताहिक

"INSPIRED INDIA. INFORMED BHARAT."

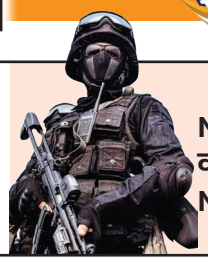
जयपुर, रविवार, 15 नवंबर 2026

INSIDE PAGE



CEO जेनसन हुआंग ने दिया इस्तीफा, अमेरिकी एजेंसियां कर रहीं जांच

पेज @ 2



NSG कमांडो की बदलेगी काली वर्दी: भीषण गर्मी से बचाने के लिए NYCO फैब्रिक का इस्तेमाल

पेज @ 5



AI से एक दशक में कैंसर और अल्जाइमर का इलाज संभव? एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल

पेज @ 6

3 साल में ₹50 करोड़ रुपए का निवेश करने पर ही मिलेगी राजस्थान में सरकारी जमीन



ITIB डेस्क | जयपुर।

राजस्थान में पर्यटन उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी जमीन आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए जमीन प्राप्त करने वाले निवेशकों को आवंटन के तीन साल के भीतर न्यूनतम 50 करोड़ का नया निवेश करना अनिवार्य होगा। राजस्व विभाग ने इसके लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। यह प्रावधान राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-B के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीन लेने के बाद निवेशक तय समय में परियोजना पर वास्तविक काम शुरू करें।

जिला कलेक्टर करेंगे जमीन चिह्नित

नई एसओपी के अनुसार, जिला कलेक्टर पर्यटन की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सरकारी जमीन की पहचान करेंगे। जमीन आरक्षित करने से पहले वहां तक सार्वजनिक पहुंच मार्ग, स्पष्ट मालिकाना हक और खसरा रिकॉर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीन आवंटित नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार लिखित कारण दर्ज कर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से जमीन आवंटित कर सकेगी।

■ शेष पेज 6 पर

दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड, AQI 494 तक पहुंचा

पराली जलाने की 5 हजार से ज्यादा घटनाएं

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 13 नवंबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 494 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, IIT दिल्ली में AQI 488, ITO में 455, आनंद विहार में 419, रोहिणी में 413 और राजोकरी बॉर्डर पर 402 दर्ज किया गया। प्रदूषण के साथ घने कोहरे ने भी राजधानी में दृश्यता कम कर दी।

पंजाब में एक दिन में पराली जलाने की 1,152 घटनाएं: दिल्ली की खराब होती हवा के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। 8 नवंबर को दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की 1,152 घटनाएं दर्ज की गईं। यह इस सीजन में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसके साथ ही 8 नवंबर तक पंजाब में कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर 4,459 हो गई थी। 10 नवंबर तक यह आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के दिन हुई घटनाओं ने पंजाब में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए दर्ज की गई पिछली प्रगति को भी पीछे छोड़ दिया। 7 नवंबर तक राज्य में 3,307 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कम थीं।

मौसम भी बन रहा प्रदूषण बढ़ने की वजह: प्रदूषण बढ़ने के पीछे केवल पराली और पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा, हवा की कम गति और वायुमंडल में प्रदूषकों के फैलने के लिए कम जगह मिलने से जहरीले कण जमीन के करीब जमा हो रहे हैं।

■ शेष पेज 6 पर



पटाखों ने भी बढ़ाया प्रदूषण का स्तर

8 नवंबर को दिवाली के दौरान पटाखों से निकले धुएं ने दिल्ली की हवा को और जहरीला बनाया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आकलन के अनुसार, 9 नवंबर की रात से अगली सुबह 1 बजे से 9 बजे के बीच दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 71.1% रही। वहीं, 13 नवंबर को पटाखों का योगदान घटकर करीब 7% रह गया, लेकिन अन्य प्रदूषण स्रोतों का प्रभाव बना रहा।

भारत ने आसान किए वीजा नियम, श्रेणियां 13 से घटाकर 9 कीं... आवेदन फॉर्म में 70% तक कम होंगे कॉलम



ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की वीजा व्यवस्था को सरल बनाते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है। इसके अलावा, वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम की संख्या भी 65 से 70 प्रतिशत तक कम की गई है।

■ शेष पेज 6 पर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026

देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची जारी... नवी मुंबई पहले स्थान पर; इंदौर की 8 साल की बादशाहत खत्म

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

देश के शहरों की स्वच्छता और सफाई व्यवस्था का आकलन करने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान हासिल किया है। वहीं, लगातार आठ वर्षों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला इंदौर इस बार पहले स्थान पर नहीं रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विजेता शहरों को सम्मानित किया।

नवी मुंबई पहले, सूरत दूसरे स्थान पर: इस बार शीर्ष तीन शहरों में नवी मुंबई पहले, गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। ये तीनों शहर सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शामिल हैं।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त करते यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। साथ में (बाएं से) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जयपुर महापौर सुनील कोठारी, यूडीएच सचिव रवि जैन और जयपुर निगम आयुक्त ओम कसेरा।

आबादी के आधार पर भी हुई रैंकिंग: सर्वेक्षण में अलग-अलग आबादी वाले शहरों के लिए अलग श्रेणियां बनाई गईं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम पहले, जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया।

■ शेष पेज 6 पर

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

जयपुर, रविवार, 15 नवंबर 2026

नेपाल के PM बालेन शाह की भारत यात्रा... चीन से लेकर सीमा विवाद तक

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) 22 से 24 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। 2025 के Gen-Z आंदोलन के बाद नेपाल में हुए राजनीतिक बदलाव और नई सरकार के गठन के बीच इस यात्रा को भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है।



भारत के लिए क्यों अहम है यह यात्रा?: भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में चीन की नेपाल में बढ़ती आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी गतिविधियों ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को भी बढ़ाया है। नेपाल इस समय बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत से सहयोग चाहता है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, इस यात्रा के दौरान पांच प्रमुख मुद्दे चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।

यात्रा के 5 प्रमुख एजेंडे

1. बाढ़ राहत और पुनर्निर्माण: नेपाल भारत से लगभग 2 अरब डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज की मांग कर सकता है। इसमें 1 अरब डॉलर की क्रेडिट सुविधा और 1 अरब डॉलर के अनुदान का प्रस्ताव शामिल बताया गया है। अगस्त 2026 की विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण इसकी प्रमुख जरूरत है।
2. हवाई और सड़क कनेक्टिविटी: नेपाल भैरहवा और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवेश मार्ग चाहता है। इसके अलावा भैरहवा-कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान और सड़क संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।
3. पंचेश्वर जलविद्युत परियोजना: महाकाली संधि के तहत प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना लंबे समय से लंबित है। इसके जरिए बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल संसाधनों का साझा उपयोग किया जा सकता है।
4. व्यापार और आर्थिक सहयोग: दोनों देश व्यापार संधि को अपडेट करने, निवेश बढ़ाने, सीमा पार व्यापार और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं।
5. सीमा विवाद और चीन का प्रभाव: नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को लेकर भारत के साथ पुराने सीमा विवाद हैं। इनके समाधान का मुद्दा भी उठ सकता है। दूसरी ओर, नेपाल में चीन की सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बढ़ती भागीदारी भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखती है।

NVIDIA में चीनी जासूसी का मामला

CEO जेनसन हुआंग ने दिया इस्तीफा, अमेरिकी एजेंसियां कर रहीं जांच



ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
दुनिया की दिग्गज AI चिप निर्माता कंपनी NVIDIA इन दिनों कथित चीनी जासूसी और CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में है।

12 नवंबर 2026 को जेनसन हुआंग ने कंपनी के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है। यह घटनाक्रम एक कथित चीनी जासूस के साथ उनके संबंधों और कंपनी की संवेदनशील तकनीक तक संभावित पहुंच को लेकर उठे सवालों के बीच हुआ।

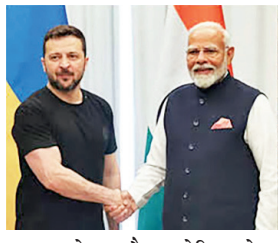
कौन हैं एलिस हुआंग?: न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एलिस हुआंग (Alice Huang) सिंगापुर की कंपनी Megaspeed International की पूर्व अधिकारी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि वह चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं। उनका जेनसन हुआंग से कथित व्यक्तिगत संबंध भी सामने आया है। हालांकि, दोनों का कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और जासूसी के आरोप अभी जांच के दायरे में हैं।

NVIDIA की AI चिप्स पर क्यों उठे सवाल?: Megaspeed पर आरोप है कि उसने अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद NVIDIA की एडवांस AI चिप्स चीनी कंपनियों तक पहुंचाने में मदद की। अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि कंपनी के जरिए चीन तक प्रतिबंधित तकनीक पहुंचाई गई। Reuters के मुताबिक, Megaspeed ने अमेरिकी अधिकारियों की जांच में सहयोग करने और अपने चिप स्टॉक की स्वतंत्र समीक्षा कराने की बात कही है।

अमेरिका-चीन के बीच बढ़ सकता है तनाव: अमेरिकी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। NVIDIA के बोर्ड ने भी स्वतंत्र जांच शुरू की है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसकी व्यापारिक गोपनीय जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा डेटा लीक हुआ है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने 2022 से चीन को अत्याधुनिक AI चिप्स की आपूर्ति पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में NVIDIA विवाद ने तकनीकी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन ने जासूसी के आरोपों को निराधार बताया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर शांति की पहल तेज... मोदी ने जेलेंस्की और जयशंकर ने लावरोव से की बातचीत

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। 9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी चर्चा की। ये बातचीत अबू धाबी में होने वाली रूस-यूक्रेन-अमेरिका की त्रिपक्षीय शांति वार्ता से ठीक पहले हुई।





अबू धाबी में 10-11 नवंबर को हुई शांति वार्ता: रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शांति वार्ता हुई। फरवरी 2026 के बाद यह पहली अमेरिकी मध्यस्थता वाली त्रिपक्षीय वार्ता थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए। वार्ता में युद्ध समाप्त करने, सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा हुई।

ब्लैक सी में खाद्यान्न आपूर्ति का प्रस्ताव: जेलेंस्की ने मोदी को युद्ध से जुड़े ताजा घटनाक्रम और अबू धाबी वार्ता की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया। जेलेंस्की के मुताबिक, भारत ने खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता की पेशकश की है।

भारत की कूटनीतिक भूमिका: मोदी ने दोहराया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। वहीं, जयशंकर और लावरोव के बीच बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और जारी कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई।

भारत के रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, जबकि यूक्रेन के साथ भी व्यापारिक और तकनीकी सहयोग है।

चीनी व्लॉगर्स के दुष्प्रचार पर भारत ने जताई आपत्ति, ढाका की झुग्गियों को बताया दिल्ली का हिस्सा

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गरीब इलाकों की तस्वीरों और वीडियो को नई दिल्ली का बताकर प्रसारित करने के मामले में आपत्ति जताई है। 10 नवंबर 2026 को मंत्रालय ने ऐसे भ्रामक प्रचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई करने की अपील की।

बांग्लादेशी अखबार 'प्रोथोम आलो' की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 150 चीनी व्लॉगर्स और लाइवस्ट्रीमर्स ढाका के उत्तरा और टेकपारा जैसे कम आय वाले इलाकों में वीडियो बना रहे थे। इन वीडियो को चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डॉयिन (Douyin) और वीचैट (WeChat) पर प्रसारित किया जा रहा था। इनमें ढाका की झुग्गियों और गलियों को नई दिल्ली का हिस्सा बताकर भारत की छवि को नकारात्मक रूप में पेश किया जा रहा था।



भारत ने क्या कहा?: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि किसी दूसरे देश की गलत तस्वीर पेश करने के ऐसे प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की।

इसके पीछे क्या हो सकता है उद्देश्य?: रिपोर्ट के अनुसार, एक चीनी प्रतिभागी ने इन वीडियो को व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों का हिस्सा बताया। हालांकि, जांच में गरीब बस्तियों को चुनकर भारत के नाम से दिखाने के उद्देश्य पर सवाल उठाए गए हैं।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत लोकेशन और भ्रामक तस्वीरों के जरिए किसी देश की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित की जा सकती है। हालांकि, इस गतिविधि के पीछे चीन सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका होने का अभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।

AI सेक्टर का बड़ा IPO: Anthropic 19 नवंबर को Nasdaq पर होगी लिस्ट... 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक वैल्यूएशन

Claude बनाने वाली कंपनी 825 मिलियन शेयर जारी करेगी, IPO से 64.35 अरब डॉलर तक जुटाने का लक्ष्य

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
AI चैटबॉट Claude बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Anthropic शेयर बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने अपने IPO के लिए प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी के शेयरों की Nasdaq पर 19 नवंबर 2026 से ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए ANT टिकर सिंबल चुना गया है। अंतिम इश्यू प्राइस 18 नवंबर को तय किया जाएगा।

64 अरब डॉलर तक जुटाने की तैयारी: Anthropic कुल 82.5 करोड़ शेयर पेश कर रही है। इनमें करीब 80.13 करोड़ नए शेयर कंपनी जारी करेगी, जबकि 2.36 करोड़ शेयर मौजूदा निवेशक बेचेंगे। ऊपरी प्राइस बैंड 78 डॉलर पर इस IPO का कुल आकार करीब 64.35 अरब डॉलर हो सकता है। कंपनी को नए शेयरों की बिक्री से करीब 62.5 अरब डॉलर मिलेंगे।



1.4 ट्रिलियन डॉलर तक वैल्यूएशन: 78 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर Anthropic का पूरी तरह डाइल्यूटेड आधार पर मूल्यांकन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। इसमें भविष्य में शेयरों में बदल सकने वाले विकल्प और अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। इनके बिना कंपनी का मूल्यांकन करीब 1 ट्रिलियन डॉलर बैठता है।

आम निवेशकों को भी मिलेगा मौका: कंपनी ने IPO में 20% तक शेयर खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए CHARLES SCHWAB, FIDELITY, ROBINHOOD और SOFI सहित छह ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का नाम सामने आया है। हालांकि, शेयरों का आवंटन मांग और उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
कई महीनों तक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली करने वाले FPI नवंबर में फिर खरीदारी करते नजर आए हैं। 12 नवंबर तक विदेशी निवेशकों ने लगातार 9 कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयर खरीदे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नवंबर में विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 12 नवंबर तक FII ने भारतीय शेयर बाजार में 73,261 करोड़ का शुद्ध निवेश किया, जो दिसंबर 2023 में बने 66,135 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इस तरह विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश दर्ज किया। यह वापसी इसलिए भी अहम है क्योंकि 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 2.95 लाख करोड़ निकाले थे।

सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट: विदेशी निवेश की खरीदारी से 12 नवंबर को सेंसेक्स 81,911 और निफ्टी 25,299 पर बंद हुए। दोनों सूचकांकों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त रही। हालांकि, 13 नवंबर को बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 319 अंक गिरकर 81,592 पर और निफ्टी 155 अंक टूटकर 25,144 पर बंद हुआ।



त्योहारों में ऑनलाइन बिक्री ₹1.41 लाख करोड़, लेकिन 2023 के बाद सबसे धीमी रफ्तार

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
भारत में 2026 के त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी 1.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। रिसर्च फर्म Datum Intelligence के अनुसार, 9 नवंबर तक 34 दिनों में कुल 1,40,800 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जो पिछले साल के 1.20 लाख करोड़ रुपये से 17% अधिक है।

हालांकि, यह 2023 के बाद सबसे धीमी सालाना बढ़ोतरी रही। बिक्री सितंबर में लगाए गए 1.50 से 1.55 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से भी कम रही।

स्मार्टफोन की बिक्री ने बिगाड़ा गणित: इस बार स्मार्टफोन की बिक्री में कमजोरी ऑनलाइन बाजार की सुस्त रफ्तार की बड़ी वजह बनी। कुल त्योहारी बिक्री में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी पिछले साल के 35.2% से घटकर करीब 25% रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट नहीं होती तो कुल ऑनलाइन बिक्री की वृद्धि करीब 22% तक पहुंच सकती थी।

ज्यादा ऑर्डर, लेकिन छोटा खर्च: लोगों ने खरीदारी तो ज्यादा की, लेकिन हर बार कम रकम खर्च की। ऑनलाइन कार्ड से औसत भुगतान 13% घटकर 5,970 रुपये रह गया, जो पिछले साल 6,830 रुपये था।

क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता: क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर 75% बढ़े, जबकि ब्रांड की अपनी वेबसाइटों पर 27-30% की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर ऑर्डर केवल 8% बढ़े।

छोटे शहरों की बढ़ती भूमिका: यूनिकॉमर्स के शुरुआती त्योहारी आंकड़ों के अनुसार, पहले सप्ताह में करीब दो-तिहाई ऑर्डर टियर-2 और टियर-3 शहरों से आए। इससे छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती पहुंच का संकेत मिलता है।

जेनसन हुआंग के इस्तीफे से NVIDIA के शेयरों में गिरावट, एक दिन में 182 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू घटी

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
दुनिया की प्रमुख AI चिप निर्माता कंपनी NVIDIA के CEO और सह-संस्थापक जेनसन हुआंग के इस्तीफे ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी। 12 नवंबर 2026 को उनके पद छोड़ने की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 14.3% तक गिर गए। हालांकि, बाद में रिकवरी हुई और शेयर 4.3% की गिरावट के साथ 166.19 डॉलर पर बंद हुआ। इस दिन कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 182 अरब डॉलर घट गया।

निवेशकों में क्यों बढ़ी चिंता?: हुआंग ने 11 नवंबर को CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। कंपनी ने 12 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की। उनके जाने से निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल कंपनी के नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर है। हुआंग पिछले 33 वर्षों से NVIDIA का नेतृत्व कर रहे थे। AI चिप कारोबार के विस्तार और बड़ी टेक कंपनियों के साथ कारोबारी संबंध बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। बाजार में इसे कंपनी के लिए 'Key Person Risk' यानी किसी एक प्रमुख व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।



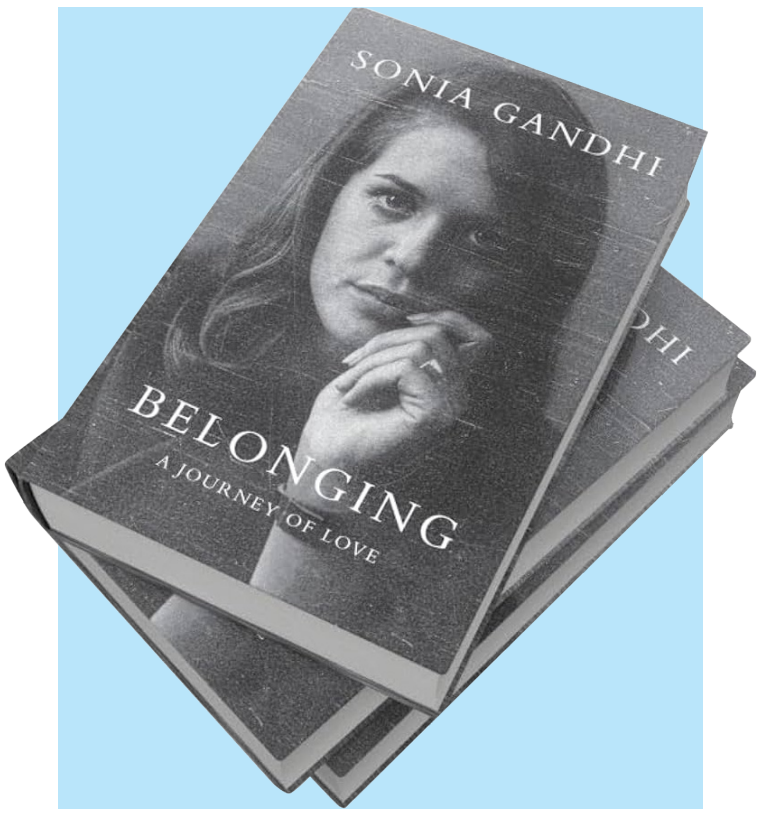
कौन संभालेगा कंपनी की कमान?: NVIDIA की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है। वह 2013 से कंपनी की वित्तीय जिम्मेदारी संभाल रही हैं और फिलहाल CFO का पद भी उनके पास रहेगा। कंपनी का बोर्ड स्थायी CEO की तलाश कर रहा है।

NVIDIA में किसकी कितनी हिस्सेदारी?: कंपनी में बड़े संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है। उपलब्ध शेयरहोल्डिंग आंकड़ों के अनुसार:

- BlackRock: 8.06%
- Vanguard Capital Management: 6.39%
- State Street: 4.19%
- FMR (Fidelity): 3.87%
- Geode Capital Management: 2.55%

अब बाजार की नजर किस पर?: NVIDIA के तिमाही नतीजे 17 नवंबर को आने वाले हैं। निवेशक कंपनी की कमाई, AI चिप की मांग और नए नेतृत्व के तहत कारोबारी निरंतरता पर नजर रखेंगे। फिलहाल शेयरों में गिरावट नेतृत्व परिवर्तन से पैदा हुई अनिश्चितता को दर्शाती है, लेकिन कंपनी के आगे के प्रदर्शन का आकलन उसके वित्तीय नतीजों से ही होगा।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र



सोनिया गांधी की किताब 'Belonging':

निजी यादों के पीछे छिपा भारत की राजनीति का इतिहास

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
किसी राजनेता की आत्मकथा सिर्फ उसके जीवन की कहानी नहीं होती, वह उस दौर को देखने का एक नजरिया भी होती है, जिसमें उसने जीवन बिताया हो। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love इसी वजह से चर्चा में है। 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित यह किताब उनके इटली के बचपन से लेकर भारत आने, राजीव गांधी से विवाह, परिवार में हुई त्रासदियों और कांग्रेस की राजनीति में उनकी भूमिका तक का सफर बयां करती है।

लेकिन इस किताब का महत्व केवल सोनिया गांधी के निजी अनुभवों तक सीमित नहीं है। नेहरू-गांधी परिवार का भारतीय राजनीति में लंबा प्रभाव रहा है। ऐसे में उनकी यादें और व्याख्याएं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का हिस्सा बनेंगी।

निजी कहानी या राजनीतिक दस्तावेज?: सोनिया गांधी ने किताब को राजनीतिक दस्तावेज के बजाय निजी अनुभवों पर आधारित संस्मरण बताया है। उनका कहना है कि वह अपने परिवार को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं, जैसा उन्होंने उसे करीब से देखा और समझा। इसमें परिवार के सदस्यों की कमजोरियों और संघर्षों का भी जिक्र है। यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की छवि अक्सर राजनीतिक विरोध, समर्थकों और मीडिया की व्याख्याओं से बनती है। आत्मकथा लेखक को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। लेकिन पाठकों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि निजी स्मृतियां और प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य एक ही चीज नहीं हैं।

प्रकाशक विवाद ने क्यों बढ़ाई चर्चा?: किताब के प्रकाशन से पहले इसका विवाद भी सुर्खियों में रहा। पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के साथ प्रकाशन को लेकर मतभेद की खबरें आईं। मीडिया रिपोर्टों में पांडुलिपि के कुछ हिस्सों में संपादकीय बदलाव और कटौती को लेकर असहमति की बात कही गई। बाद में हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने किताब प्रकाशित करने की घोषणा की। हालांकि, पेंगुइन ने स्पष्ट किया कि प्रकाशन से अलग होने की परिस्थितियों को केवल संपादकीय बदलावों से जोड़ना सही नहीं है। इस घटनाक्रम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रकाशकीय जिम्मेदारी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री के संपादन पर सवाल खड़े किए। लेकिन बिना प्रमाण इसे किसी राजनीतिक दबाव या सेंसरशिप का निश्चित मामला मानना उचित नहीं होगा।

इतिहास पर अपना पक्ष रखना और जवाबदेही: किताब को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और आपातकाल जैसे विवादास्पद अध्यायों को अपने परिवार के पक्ष में प्रस्तुत किया है। वहीं, सोनिया गांधी ने 1984 की हिंसा को दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है तथा न्याय में हुई देरी पर भी बात की है। यहीं इस किताब को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामने आता है। किसी भी नेता को अपने जीवन और घटनाओं का पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन इतिहास की व्याख्या केवल एक व्यक्ति की स्मृतियों के आधार पर अंतिम सत्य नहीं बन सकती। उसे सरकारी दस्तावेजों, न्यायिक रिकॉर्ड, समकालीन रिपोर्टों और दूसरे प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों के साथ पढ़ना चाहिए।

₹500 के नोट बंद हों: सीएम नायडू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़े नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की मांग की

₹500 के नोट को प्रचलन से बाहर करने की चंद्रबाबू नायडू की मांग ने नोटबंदी के अनुभवों और भारत की नकदी आधारित अर्थव्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है।



ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
भ्रष्टाचार, कालेधन और चुनावों में धनबल के इस्तेमाल की चर्चा होते ही बड़े मूल्यवर्ग के नोटों पर सवाल उठने लगते हैं। इसी सोच के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2,000 के नोटों को प्रचलन से हटाने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि बड़े नोटों की उपलब्धता अवैध नकदी के लेन-देन को आसान बनाती है। लेकिन सवाल है कि क्या बड़े नोट हटाने भर से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है या इससे नकदी पर निर्भर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी?

नोट का आकार और भ्रष्टाचार का विस्तार

बड़े मूल्यवर्ग के नोटों में अधिक नकदी रखना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। यही नायडू की मांग का आधार है। उनका मानना है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने से लेन-देन का रिकॉर्ड बनेगा और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी आसान होगी। हालांकि, भ्रष्टाचार केवल नकदी तक सीमित नहीं है। रिश्वत और अवैध कमाई का पैसा जमीन, सोने, बेनामी संपत्ति, विदेशी खातों और फर्जी कंपनियों में भी लगाया जाता है। इसलिए बड़े नोट हटाना भ्रष्टाचार के एक माध्यम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे पूरी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता।

500 के नोट की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भूमिका?: RBI की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 के अंत तक प्रचलन में मौजूद बैंक नोटों के कुल मूल्य में 500 के नोटों की हिस्सेदारी 85.5 प्रतिशत थी। यानी कागजी मुद्रा के मूल्य का बड़ा हिस्सा इसी नोट में है। ऐसे में 500 के नोट को हटाना सामान्य मुद्रा परिवर्तन नहीं होगा। इसका असर छोटे व्यापारियों, किसानों, खुदरा बाजार और नकदी पर निर्भर लोगों पर पड़ सकता है। 100 और 200 के नोटों में समान रकम रखने के लिए अधिक नोटों की जरूरत होगी। इससे नकदी संभालने, गिनने और वितरण की चुनौती बढ़ेगी। बैंकों और एटीएम में छोटे नोटों की मांग भी बढ़ सकती है।

डिजिटल भुगतान भी पूरी तरह आसान विकल्प नहीं

नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। फर्जी UPI लिंक, OTP धोखाधड़ी और बैंकिंग खातों के दुरुपयोग की घटनाएं चिंता का विषय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता भी हर जगह समान नहीं है। इसलिए डिजिटल व्यवस्था मजबूत किए बिना नकदी को सीमित करना व्यावहारिक मुश्किलें पैदा कर सकता है।

2016 की नोटबंदी से क्या सबक मिला?

8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों का वैध मुद्रा का दर्जा समाप्त कर दिया था। उस समय प्रचलन में मौजूद कुल मुद्रा के मूल्य का लगभग 86.9 प्रतिशत हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। नकदी की अचानक कमी के कारण आम नागरिकों, किसानों और छोटे कारोबारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालेधन पर इसके असर को लेकर भी सवाल उठे। RBI के आंकड़ों के अनुसार, नोटबंदी के दौरान वापस आने योग्य पुराने नोटों में से लगभग 99 प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में लौट आए। इससे स्पष्ट हुआ कि नकदी के रूप में मौजूद कालेधन को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर अपेक्षित नतीजे नहीं मिले।

क्या 500 रुपये के नोट को हटाना व्यावहारिक है?

यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो उसे पहले व्यापक आर्थिक अध्ययन करना होगा। छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की जरूरत और डिजिटल भुगतान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी। एक विकल्प यह हो सकता है कि नए ₹500 के नोटों की छपाई और आपूर्ति धीरे-धीरे कम की जाए, ताकि बाजार में अचानक नकदी संकट पैदा न हो।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नोटों से आगे बढ़े

भ्रष्टाचार की जड़ केवल बड़े नोट नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद अपारदर्शिता भी है। सरकारी ठेकों, राजनीतिक चंदे, बेनामी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई भी जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू की मांग एक महत्वपूर्ण आर्थिक बहस जरूर खड़ी करती है, लेकिन किसी भी फैसले में आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े नोट हटाना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उपाय हो सकता है, संपूर्ण समाधान नहीं। असली सुधार तब होगा जब अवैध कमाई के रास्तों के साथ उस व्यवस्था पर भी प्रभावी कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर देती है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

यूक्रेन युद्ध के बाद गोला-बारूद की मांग बढ़ी

भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय देशों को किया बड़े पैमाने पर निर्यात

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
यूरोप में बढ़ते रक्षा खर्च और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गोला-बारूद की मांग ने भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के नए अवसर खोले हैं। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड *38,424 करोड़ रुपये* तक पहुंच गया। भारतीय कंपनियां अब यूरोप के कई देशों को आर्टिलरी शेल, गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रही हैं।



■ यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई मांग

फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया। इससे उनके अपने सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ा। अब यूरोपीय देश खाली हुए भंडार को दोबारा भरने और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद के चार वर्षों में भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय देशों को कम से कम 872 मिलियन डॉलर का गोला-बारूद निर्यात किया। युद्ध से पहले के चार वर्षों में यह आंकड़ा 49.2 मिलियन डॉलर था।

■ रोमानिया और स्लोवेनिया बने खरीदार

भारतीय रक्षा उत्पादों के प्रमुख यूरोपीय खरीदारों में रोमानिया, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में आर्टिलरी शेल, मोर्टार, छोटे-बड़े कैलिबर का गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं।

■ 'रीआर्म यूरोप' योजना से बढ़ेंगे अवसर

यूरोपीय संघ की 'रीआर्म यूरोप' पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में 800 अरब यूरो से अधिक के निवेश की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य सैन्य उत्पादन और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में कारोबार के नए अवसर बन सकते हैं।

■ भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती

भारतीय गोला-बारूद के यूरोपीय खरीदारों के माध्यम से यूक्रेन पहुंचने के दावे भी सामने आए हैं। हालांकि, भारत ने सीधे यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति नहीं की है। भारत के लिए चुनौती यूरोपीय रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ रूस के साथ पुराने रक्षा संबंधों और कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने की भी है। सरकार ने 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यूरोप की बढ़ती मांग इस लक्ष्य में मददगार हो सकती है।

NSG कमांडो की बदलेगी काली वर्दी

भीषण गर्मी से बचाने के लिए NYCO फैब्रिक का इस्तेमाल

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
भारत के ब्लैक कैट कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की मशहूर काली वर्दी में बदलाव होने जा रहा है। NSG ने VIP सुरक्षा में तैनात कमांडो के लिए हल्की और सांस लेने योग्य (Breathable) यूनिफॉर्म की सिफारिश की है। इसके लिए नायलॉन और कॉटन के मिश्रण वाले NYCO फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य गर्मी और लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानी को कम करना है।

44 डिग्री तापमान में बेहोश हुआ था कमांडो

यह फैसला अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई घटना के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक NSG कमांडो करीब 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गया था।

कमांडो ने काली ओवरऑल यूनिफॉर्म के ऊपर करीब 6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी। इसके अलावा हथियार और संचार उपकरण भी साथ थे। इस घटना के बाद NSG ने VIP सुरक्षा में तैनात जवानों की वर्दी और उपकरणों से जुड़ी चुनौतियों का आकलन किया।

क्या है NYCO फैब्रिक?

NYCO नायलॉन और कॉटन से बना मिश्रित कपड़ा है। यह हवा और नमी की भाप को बाहर निकलने देता है, जिससे शरीर को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। CRPF के CoBRA कमांडो भी इस फैब्रिक की यूनिफॉर्म पहनते हैं।

कब मिलेगी नई यूनिफॉर्म?

नई यूनिफॉर्म का ट्रायल पूरा हो चुका है। NSG जल्द ही कपड़े की खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। उम्मीद है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कमांडो नई वर्दी में नजर आ सकते हैं।



भारतीय नौसेना के 60 दिन में 11 युद्धाभ्यास

बढ़ती ताकत या संसाधनों पर दबाव?



ITIB डेस्क | नई दिल्ली।
भारतीय नौसेना ने सितंबर से नवंबर 2026 के बीच 60 दिनों से कम समय में 11 अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में हिस्सा लिया। ये अभ्यास ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, दक्षिण कोरिया और ओमान सहित कई देशों के साथ अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों में हुए। यह भारत की बढ़ती समुद्री पहुंच और वैश्विक भूमिका का संकेत है। हालांकि, इससे सवाल उठ रहा है कि क्या सीमित संसाधनों वाला नौसेना बेड़ा इतने व्यापक अभियानों का दबाव संभाल सकता है।

किन देशों के साथ हुए अभ्यास?: इस अवधि में श्रीलंका के साथ SLINEX, फ्रांस के साथ VARUNA, ब्रिटेन के साथ KONKAN, रूस के साथ INDRA, सिंगापुर के साथ SIMBEX, दक्षिण कोरिया के साथ IN-RoKN और अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ MALABAR अभ्यास हुआ। इसके अलावा IBSAMAR, ADMM-Plus, AIME और ओमान के साथ NASEEM AL BAHR भी आयोजित हुए।

क्या नौसेना पर बढ़ रहा है दबाव?: इन अभ्यासों से नौसेना को समुद्री निगरानी, संचार, संयुक्त अभियानों और युद्धक रणनीतियों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, पुरानी होती पनडुब्बियां, सीमित बेड़ा और नए युद्धपोतों के निर्माण में देरी चुनौती हैं।

भारत के सामने क्या चुनौती है?

भारत को हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा और निगरानी क्षमता बनाए रखते हुए पश्चिमी प्रशांत और अन्य समुद्री क्षेत्रों में भी सक्रिय रहना है। इसके लिए नए युद्धपोतों, पनडुब्बियों, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में निवेश जरूरी है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

जयपुर, रविवार, 15 नवंबर 2026

पेज 1 का शेष...

3 साल में ₹50 करोड़...

ऑनलाइन मिलेगी जमीन की जानकारी: पारदर्शिता के लिए आरक्षित जमीन का विवरण जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें जिला, तहसील, गांव, खसरा नंबर, क्षेत्रफल और परियोजना श्रेणी के साथ क्यूआर कोड और गूगल लोकेशन भी उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ सरकारी जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। तीन साल में निवेश की अनिवार्यता से परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद है।

दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड...

स्वास्थ्य पर गंभीर असर, GRAP के तहत कार्रवाई: AQI 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में आता है। इस स्तर पर स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जबकि बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा अधिक रहता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-NCR में GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, हर साल सर्दियों में सामने आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है, जब पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण पर पूरे साल प्रभावी नियंत्रण किया जाए।

भारत ने आसान किए वीजा नियम...

सरकार का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों, छात्रों, मरीजों, निवेशकों और कारोबारियों के लिए भारत आना आसान बनाना है।

पहले भी हुआ था वीजा व्यवस्था में बदलाव: गृह मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव 27 अगस्त 2026 को किया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था। सरकार ने समान उद्देश्यों वाली वीजा श्रेणियों को एक साथ मिलाकर आवेदन प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयास किया है।

टूरिस्ट वीजा की जगह अब विजिटर वीजा: नई व्यवस्था में पुराने टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसे दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।

- V-1 वीजा: 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री की सुविधा। इसमें पर्यटन के अलावा बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट और छोटे अवधि के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कोर्स शामिल हैं।
- V-2 वीजा: 1, 5 और 10 साल की वैधता के साथ जारी किया जा सकेगा। इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल है।

मेडिकल और स्टूडेंट वीजा में भी बदलाव: मेडिकल वीजा को सामान्य चिकित्सा और आयुष उपचार के आधार पर अलग किया गया है। M-1 सामान्य चिकित्सा उपचार, जबकि M-3 आयुष उपचार के लिए होगा। इनके साथ आने वाले मरीजों के अटेंडेंट के लिए क्रमशः M-2 और M-4 वीजा की व्यवस्था की गई है। इन मेडिकल वीजा श्रेणियों में सामान्यतः एक साल की वैधता और मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। स्टूडेंट वीजा को S-1 और S-2 में बांटा गया है। S-1 स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए, जबकि S-2 रिसर्च, PhD, इंटर्नशिप और एक्सचेंज कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए होगा।

बिजनेस वीजा की श्रेणियां भी हुईं स्पष्ट: बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया है। B-1 के तहत लंबे समय की लाइसेंस आधारित व्यावसायिक गतिविधियां और भारत में उद्योग या कारोबार स्थापित करना शामिल है। वहीं, B-2 छोटी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम, सम्मेलन, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए है। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। भारत की नई वीजा व्यवस्था में कुल 9 मुख्य श्रेणियां होंगी—बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसलेनियस वीजा।

कब से लागू होगी नई व्यवस्था?: गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवेदन फॉर्म के जरूरी कॉलम 65-70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं, जबकि वीजा प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी बरकरार रखी गई है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपडेट कर रहा है। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026...

नदी और तटीय शहरों को भी मिली पहचान: इस बार नदी किनारे बसे शहरों, तटीय शहरों और हिमालयी क्षेत्रों के लिए भी अलग पुरस्कार दिए गए। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा पहले, बिलासपुर दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, स्वच्छ कोस्टल टाउन श्रेणी में पुरी पहले स्थान पर रहा।

कैसे तय होती है शहरों की रैंकिंग?: स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत किया जाता है। इस बार देश के 4,751 शहरी स्थानीय निकायों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। शहरों का मूल्यांकन कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का अलग-अलग प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, कचरे के प्रसंस्करण और नागरिकों की भागीदारी जैसे मानकों पर किया गया।

यह सर्वेक्षण देश में शहरी स्वच्छता की स्थिति का आकलन करने के साथ नगर निकायों के बीच बेहतर सफाई व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

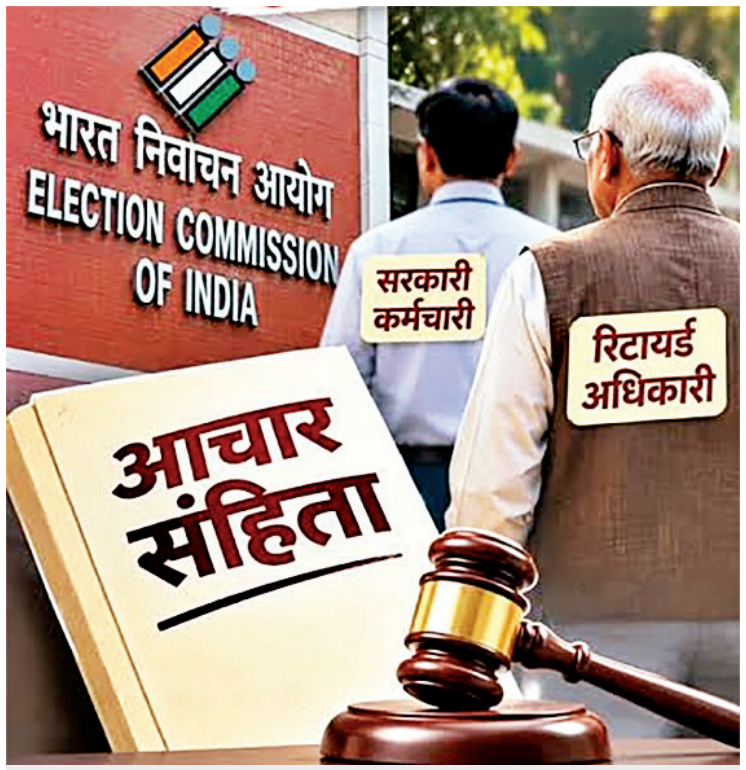
रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct-MCC) के नियम लागू कर दिए हैं। अब ऐसे अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही अपनी आधिकारिक हैसियत या प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने 9 नवंबर 2026 को इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा। इन पांच राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

किन अधिकारियों पर लागू होंगे ये निर्देश?: यह आदेश सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके दायरे में वे अधिकारी और कर्मचारी आएंगे, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दोबारा नियुक्त किया गया है या किसी पद अथवा जिम्मेदारी के साथ जोड़ा गया है। आयोग के अनुसार, नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े स्पष्ट नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्तियों के लिए चुनाव अवधि के दौरान ऐसे प्रतिबंधों को स्पष्ट करना जरूरी था।

चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक: नए निर्देशों के तहत संबंधित अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार, राजनीतिक सभाओं और कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वे अपनी आधिकारिक पदवी, नाम या सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, जिन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां ये अधिकारी चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आधिकारिक बैठक या चर्चा के लिए नहीं बुला सकेंगे। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यमों से बैठक करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।



उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि इन नियमों की जानकारी सभी विभागों और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाई जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और सरकारी मशीनरी के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकना है। इस फैसले के जरिए चुनाव आयोग ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को भी चुनावी अवधि में राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने का दायरा स्पष्ट किया है।

यूपी चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा', चंद्रशेखर होंगे CM चेहरा

ITIB डेस्क | लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गठबंधन का ऐलान किया है। गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा। मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है।

दलित-मुस्लिम समीकरण पर नजर: गठबंधन की रणनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% और दलित आबादी लगभग 21% है। दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40% बैठती है। हालांकि, आबादी का यह आंकड़ा सीधे वोट में तब्दील होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।



अखिलेश ने किया स्वागत, भाजपा को नुकसान का दावा: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चे का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक बदलाव जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि इस नए विकल्प से भाजपा को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का नुकसान हो सकता है। वहीं, सपा के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने चंद्रशेखर को ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर सावधान रहने की सलाह दी। RLD नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस गठबंधन से NDA की सफलता पर असर नहीं पड़ेगा, हालांकि चुनाव प्रचार में आक्रामकता बढ़ सकती है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

छठ महापर्व शुरू: 15 नवंबर को डूबते और 16 नवंबर को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

■ **दिल्ली में 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, मूनक नहर पर बना 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट; 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश**

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार, 13 नवंबर से शुरू हो गया है। सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित इस पर्व में व्रती संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए कठिन अनुष्ठान करते हैं। पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से हुई। शनिवार, 14 नवंबर को खरना मनाया जा रहा है। इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा।

चार दिन ऐसे होंगे प्रमुख अनुष्ठानः 13 नवंबरः नहाय-खाय – पहले दिन व्रती स्नान और घर की साफ-सफाई के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का विशेष महत्व है।



■ **14 नवंबरः खरना** – दूसरे दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है। इसके बाद निर्जला व्रत शुरू होता है।

■ **15 नवंबरः संध्या अर्घ्य** – तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब और घाटों पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूप और दउरा में फल, नारियल और ठेकुआ सहित पूजन सामग्री सजाई जाएगी।

■ 16 **नवंबरः उषा अर्घ्य**- अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती व्रत का पारण करेंगे। इसी के साथ पर्व का समापन होगा।

दिल्ली में सुरक्षा के विशेष इंतजामः दिल्ली में छठ पूजा के लिए 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। यमुना घाटों, तालाबों और प्रमुख पूजा स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों पर विशेष ध्यान रहेगा। मूनक नहर के दोनों किनारों पर करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट विकसित किया गया है। दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर को सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दिल्ली के सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी इस दिन बंद रहेंगे। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद के लिए गेहूं को धोने, सुखाने और पीसने तक साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही परंपराएं इस पर्व को लोक आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनाती हैं।

दिल्ली की जहरीली हवा का असर
सिर्फ सात दिन में फेफड़ों और दिल पर पड़ सकता है गंभीर प्रभाव

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता बनती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक प्रदूषित हवा में केवल एक सप्ताह तक रहने से भी फेफड़ों और हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, PM2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कण कुछ ही दिनों में शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं।

फेफड़ों पर क्या होता है असर?: PM2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों की सबसे अंदरूनी वायु थैलियों तक पहुंच सकते हैं। इससे खांसी, गले में जलन, सांस लेने में परेशानी, घरघराहट और बलगम बनने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अस्थमा और COPD के मरीजों में इसके लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।

रक्त वाहिकाओं पर खतराः प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता। PM2.5 के संपर्क से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इससे ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन और रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। पहले से हृदय रोग, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है।



कैसे करें बचाव?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण अधिक होने पर अनावश्यक बाहरी गतिविधियों और खुले में व्यायाम से बचना चाहिए। बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें और घर की खिड़कियां बंद रखें। सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द होने पर चिकित्सकीय सहायता लें।

विशेषज्ञों का कहना है कि एक सप्ताह प्रदूषित हवा में रहने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाएगी, लेकिन कम समय का संपर्क भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

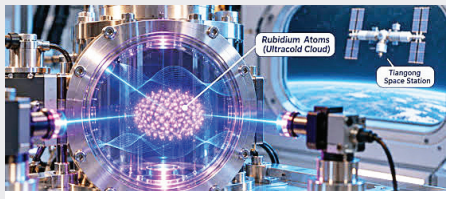
चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया सबसे ठंडा तापमान, परम शून्य से सिर्फ 9.7 पिकोकैल्विन ऊपर पहुंचाए परमाणु

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

चीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया है। चीन के तियांगोंग (Tiangong) स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के एक समूह को 9.7 पिकोकैल्विन (Picokelvin) तक ठंडा किया। यह तापमान ब्रह्मांड के औसत बैकग्राउंड तापमान से लगभग 280 अरब गुना कम है। इस शोध को 5 नवंबर 2026 को प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका Science में प्रकाशित किया गया।

कैसे हासिल किया इतना कम तापमान?: इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने रूबिडियम-87 के लगभग 20,000 परमाणुओं का इस्तेमाल किया। लेजर तकनीक और विशेष मैग्नेटिक व्यवस्था की मदद से इन्हें ठंडा करके बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (Bose-Einstein Condensate) बनाया गया। यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था है, जिसे अक्सर पदार्थ की पांचवीं अवस्था कहा जाता है। इसमें अत्यधिक ठंडे परमाणु अलग-अलग कणों की तरह व्यवहार करने के बजाय एक सामूहिक क्वांटम तरंग की तरह व्यवहार करने लगते हैं।

अंतरिक्ष में ही क्यों किया गया प्रयोग?: पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण अत्यधिक ठंडे परमाणुओं को लंबे समय तक स्थिर रखना मुश्किल होता है। लेकिन तियांगोंग स्पेस स्टेशन के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में वैज्ञानिकों को परमाणुओं को अधिक समय तक नियंत्रित करने का अवसर मिला। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक परमाणुओं के बादल को मुक्त रूप से फैलते हुए लगभग 7 सेकंड तक देख सके।



क्या है परम शून्य और इसका महत्व?

परम शून्य (Absolute Zero) तापमान की सैद्धांतिक न्यूनतम सीमा है, जो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। वैज्ञानिक इसे हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस उपलब्धि से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग, अत्यधिक संवेदनशील सेंसर, गुरुत्वाकर्षण मापन और अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
नोट: 9.7 पिकोकैल्विन परमाणुओं के विस्तार से निकाला गया समतुल्य तापमान है, पूरे स्पेस स्टेशन या उसके वातावरण का तापमान नहीं। 280 अरब गुना की तुलना ब्रह्मांड के लगभग 2.7 केल्विन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तापमान से है।

इंडिया ITIB दैट इज भारत
साप्ताहिक समाचार पत्र

AI से एक दशक में कैंसर और अल्जाइमर का इलाज संभव?

दावे पर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले दशक में कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह दावा AI चैटबॉट Claude बनाने वाली कंपनी Anthropic के CEO डारियो अमोदेई ने किया है। उनका मानना है कि AI की मदद से अगले 10 वर्षों में ऐसी बीमारियां, जिनका इलाज आज बेहद चुनौतीपूर्ण है, अतीत की बात बन सकती हैं। हालांकि, मेडिकल और फार्मा विशेषज्ञों ने इस समयसीमा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।



AI कैसे बदल सकता है दवाओं की खोज?: अमोदेई के अनुसार, AI शरीर में बीमारियों के कारणों को समझने, नए ड्रग टारगेट खोजने और दवाओं के डिजाइन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इस दिशा में Google DeepMind का AlphaFold एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस AI सिस्टम ने 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी की है। इससे वैज्ञानिकों को प्रोटीन की संरचना समझने और नई दवाओं पर शोध करने में मदद मिल रही है।

फार्मा विशेषज्ञों ने दावे पर उठाए सवाल

Vertex Pharmaceuticals के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ लेडेन ने AI से कुछ ही वर्षों में अधिकांश बीमारियों का इलाज खोजने के दावों को 'बकवास' बताया। उनके अनुसार, AI कंपनियों के साथ प्रयोग और हजारों ड्रग कंपाउंड का विश्लेषण करने के बावजूद प्रभावी दवा विकसित करना आसान नहीं है।

AI से बनी दवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं?: AI किसी संभावित दवा का डिजाइन तैयार कर सकता है, लेकिन उसके सुरक्षित और प्रभावी होने की पुष्टि लैब परीक्षणों और इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही होती है। दुष्प्रभाव, सही खुराक और लंबे समय के परिणामों की जांच जरूरी है। 2026 तक किसी पूरी तरह AI-डिजाइन की गई दवा को FDA से बाजार में बिक्री की मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए AI चिकित्सा अनुसंधान की गति बढ़ा सकता है।

Instagram पर AI से होगी उम्र की पहचान, करोड़ों को मिलेंगी अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram की पैरेंट कंपनी Meta ने दुनिया भर में AI आधारित एज डिटेक्शन तकनीक का विस्तार करने की घोषणा की है। 9 नवंबर 2026 को घोषित इस फैसले का उद्देश्य ऐसे किशोरों की पहचान करना है, जो अकाउंट बनाते समय अपनी वास्तविक उम्र छिपाकर खुद को 18 साल या उससे अधिक बताते हैं। कंपनी के मुताबिक, इस कदम से दुनिया भर के लाखों अतिरिक्त किशोरों को Instagram के Teen Account सुरक्षा फीचर्स के दायरे में लाया जाएगा।

कैसे काम करेगी AI तकनीक?

Meta की AI तकनीक यूजर की बताई गई जन्मतिथि पर ही निर्भर नहीं रहेगी। यह प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट, बायो और कैप्शन में मौजूद संकेतों का विश्लेषण करेगी। उदाहरण के लिए, जन्मदिन की पोस्ट, स्कूल की कक्षा या पढ़ाई से जुड़े उल्लेखों के आधार पर AI अनुमान लगा सकती है कि अकाउंट किसी किशोर का है। यदि सिस्टम को लगता है कि यूजर की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच है, तो उसे Teen Account सुरक्षा व्यवस्था में रखा जा सकता है, भले ही उसने प्रोफाइल में वयस्क उम्र दर्ज की हो।



Teen Account में क्या मिलेंगी सुविधाएं?

इस व्यवस्था के तहत किशोरों के अकाउंट पर कई सुरक्षा प्रतिबंध स्वतः लागू होते हैं:

- अनजान लोगों के मैसेज और संपर्क पर सीमाएं।
- संवेदनशील और अनुचित कंटेंट की दृश्यता कम करना।
- अकाउंट को डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट रखना।
- रात के समय नोटिफिकेशन और ऐप इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
- 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के लिए कुछ सेटिंग बदलने में माता-पिता की अनुमति।

Facebook और Threads पर भी विस्तार

Meta के अनुसार, Facebook पर भी AI आधारित उम्र पहचानने वाली तकनीक का विस्तार जारी है। कंपनी इस साल के अंत तक Threads पर भी इसी तरह की तकनीक शुरू करने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया में Meta ने Apple के Age-Range Signal का इस्तेमाल भी शुरू किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब Meta को किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा और सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य किशोरों को उनकी उम्र के अनुसार सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना है।

द. महासागर में बढ़ा ऑक्सीजन का स्तर, ग्लोबल ट्रेंड से अलग दिखा बदलाव; NCPOR का खुलासा

ITIB डेस्क | नई दिल्ली।

दुनिया के अधिकांश महासागरों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है, लेकिन दक्षिणी महासागर के भारतीय क्षेत्र में इसके विपरीत बदलाव देखने को मिला है। गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1993 से 2025 के बीच इस क्षेत्र में समुद्र के पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह अध्ययन 30 अक्टूबर 2026 को Environmental Research Letters जर्नल में प्रकाशित हुआ।



समुद्री जीवन और जलवायु के लिए महत्व

घुली हुई ऑक्सीजन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसके स्तर में वृद्धि से गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ मिल सकता है। दक्षिणी महासागर वैश्विक ताप, कार्बन और पोषक तत्वों के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्रीय बदलाव है। इसे दुनिया के महासागरों में ऑक्सीजन की कमी खत्म होने का संकेत नहीं माना जा सकता।

300 से 2,000 मीटर की गहराई में सबसे ज्यादा वृद्धि

अध्ययन में सबसे अधिक ऑक्सीजन वृद्धि 300 से 2,000 मीटर की गहराई के बीच दर्ज की गई। अंटार्कटिक क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर प्रति वर्ष प्रति किलोग्राम पानी में 2.37 माइक्रोमोल और ध्रुवीय क्षेत्र में 1.41 माइक्रोमोल बढ़ा। वहीं, 2,000 से 5,000 मीटर की गहराई में भी ऑक्सीजन बढ़ने के संकेत मिले। शोधकर्ताओं ने 2011 और 2025 के समुद्री सर्वेक्षणों के साथ 1993 से 2025 तक के उपग्रह और महासागरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया। मध्यवर्ती जल परतों में ऑक्सीजन की मात्रा 2011 के लगभग 4.5 मिलीलीटर प्रति लीटर से बढ़कर 2025 में 5.5 मिलीलीटर प्रति लीटर हो गई।

ऑक्सीजन बढ़ने की क्या है वजह?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका प्रमुख कारण बेहतर महासागरीय वेंटिलेशन (Ocean Ventilation) है। तापमान और खारेपन में बदलाव से समुद्र की विभिन्न जल परतों के बीच घनत्व का अंतर कमजोर हुआ है। इससे सतह का ऑक्सीजन युक्त पानी गहराई तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा समुद्री धाराओं में बदलाव और जैविक उत्पादन में वृद्धि ने भी इसमें योगदान दिया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक अंकित कुमार अवस्थी के लिए स्काईटेक प्रिन्टर्स, 111 नवाब कल्लन का बाग, एम आई रोड़ से मुद्रित होकर, प्लाट नंबर 53 महादेव नगर, जयपुर से प्रकाशित।
*प्रधान संपादक अंकित कुमार अवस्थी (समाचार चयन के लिए पी आर पी एक्ट के तहत जिम्मेदार) RNI NO RAJHIN26/A8486